

मनुष्य कितना भी गौरा क्यों न हो, परंतु उसकी परछाई हमेशा ही काली होती है।

- अज्ञात

लड़ाई में कौन किस तरफ

खास बात यह कि इस बार दोनों ही चुनावी खेमों में छोटे दलों को तवज्जो न देने का रुझान दिखाई दे रहा है। सिर्फ अपनी तरफ से यह स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री का चेहरा गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी तय करेगी।

नवीन शाह।

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें भले न घोषित हुई हों पर चुनावी तैयारी से जुड़ी हलचलें चरम पर हैं। लड़ाई में कौन किस तरफ और किस कीमत पर रहेगा, इसे लेकर भी गतिविधियां तेज हो रही हैं। खास बात यह कि इस बार दोनों ही चुनावी खेमों में छोटे दलों को तवज्जो न देने का रुझान दिखाई दे रहा है। विपक्षी गठबंधन की बात करें तो इसमें शामिल आरएलएसपी जैसे दल मुख्यमंत्री प्रत्याशी का सवाल उठाते हुए काफी पहले से यह कहने लगे थे कि नीतीश कुमार के सामने आरजेडी के युवा नेता तेजस्वी यादव फिट नहीं बैठते। मगर आरजेडी ने इस सवाल पर ध्यान देना तो दूर, गठबंधन सहयोगियों के साथ बैठना भी जरूरी नहीं समझा। सिर्फ अपनी तरफ से यह स्पष्ट कर दिया

कि मुख्यमंत्री का चेहरा गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी तय करेगी।

इसी तरह सत्तारूढ़ एनडीए में एलजेपी नेता चिराग पासवान लगातार बिहार सरकार और नीतीश कुमार पर हमले कर रहे हैं, लेकिन एनडीए नेतृत्व उनके बयानों का नोटिस ही नहीं ले रहा। माना जा रहा है कि उनकी कोशिश तालमेल में ज्यादा सीटें पाने की है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी का तर्क है कि ज्यादा सीटों पर लड़ने से ज्यादा सीटें नहीं आ जातीं। पिछले विधानसभा चुनाव में 42 सीटों पर लड़कर एलजेपी महज दो सीटें जीत पाई थी। कुल मिलाकर इस बार मुकाबला दो दल (जेडीयू-बीजेपी) बनाम दो दल (आरजेडी-कांग्रेस) का बनता दिख रहा है। दूसरी खास बात यह कि विपक्ष तो

हमेशा की तरह सरकार की गड़बड़ियों और नाकामियों को मुद्दा बना रहा है, पर सत्तापक्ष नई पिच की तलाश में है।

नीतीश कुमार आम तौर पर अपनी सरकार के कामकाज को ही मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ते रहे हैं, पर इस बार उन्होंने 15 साल पहले के लालू शासन को यानी बिहार के कथित जंगल राज को मुद्दा बनाने की कोशिश की। यह और बात है कि पिछले चुनाव में ही आरजेडी के साथ उनका सफल महागठबंधन प्रयोग उनके आड़े आ गया। स्वाभाविक रूप से एनडीए को बिहार में किसी तगड़े भावनात्मक मुद्दे की जरूरत थी।

बीजेपी के पास हिंदुत्व के रूप में ऐसा एक रेडीमेड मुद्दा हमेशा उपलब्ध रहता है लेकिन बिहार में उसका हिंदुत्व कार्ड

अबतक एक बार भी बाकी राज्यों जितना नहीं चल पाया है। राष्ट्रवाद जरूर चलता है, जैसा पिछले आम चुनाव के दौरान बिहार के वोटों पर पुलवामा कांड के असर से जगजाहिर है, पर हिंदुत्व नहीं चलता। यही वजह है कि यहाँ बीजेपी को जेडीयू का छोटा भाई बनकर ही रहना पड़ता है। बहरहाल, इन सबका मिला-जुला परिणाम यह हुआ कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को सत्ता पक्ष की ओर से जबर्दस्त भावनात्मक रंग दिया जा रहा है और विपक्ष इसे मौन समर्थन देने के सिवा कुछ कर नहीं पा रहा। इस क्रम में पहली बार एक हिंदीभाषी राज्य में क्षेत्रीय अस्मिता बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर उभरी है, हालांकि यह किस हद तक वोटों में बदलती है, इसका पता चुनाव नतीजे आने के बाद ही चलेगा।

श्रीअमरनाथ

अशोक वोहरा।

श्रीअमरनाथ का मंदिर कश्मीर के बारह हजार सात सौ बानबे फीट ऊँचे एक पर्वत शिखर पर स्थित है। यह देश के सबसे महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थलों में से एक है। प्रतिवर्ष श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन के दिन देश के कोने-कोने से हजारों तीर्थयात्री यहाँ की यात्रा करके पुण्यलाभ करने आते हैं। यह स्थान कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से सत्तासी मील पूर्व में स्थित है। श्रीअमरनाथ का मार्ग हिमालय के सभी तीर्थस्थानों के मार्ग से कठिन है। चढ़ाई दुर्गम है, शीत भयंकर है। तूफानी बर्फाली हवाओं के कारण यात्रियों को कदम-कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इनकी चिंता किए बिना क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या स्त्रियाँ, क्या बालक मंदिर के दर्शनों को चल पड़ते हैं। भक्तों का विश्वास है कि यह स्वर्ग की सीढ़ी है।

धर्म-दर्शन



संपादकीय

जेब खाली, पेट खाली

यह ठीक है कि अब बाजार खुलने लगे हैं और कारखाने चलने लगे हैं लेकिन ग्राहक कहाँ हैं? दुकानों का माल खरीदेगा कौन? लोगों की जेबें खाली हैं। देश में 70-80 करोड़ लोग तो ऐसे हैं, जिनके पेट भी खाली हैं। वे रोज कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं। यदि सरकार और समाज ने उनकी खबर नहीं ली तो देश में अराजकता फैलने में कोई कसर नहीं रहेगी। मरता, क्या नहीं करता? सिर्फ लपफाजी से काम नहीं चलेगा। इस वक्त जरूरी यह है कि लोगों के हाथ में पैसा पहुंचे ताकि वे खरीदारी कर सकें। सरकार शीघ्र ही आवश्यक कदम उठाएगी लेकिन सरकार से भी ज्यादा समाज की जिम्मेदारी है। कई गुरुद्वारे, मंदिर, जैन-संस्थाएं, मस्जिदें, गिरजे, संघ और समाजसेवी संस्थाएं उत्तम पहल कर रही हैं लेकिन राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं? इनके 10-12 करोड़ सदस्य यदि दो-दो तीन-तीन परिवारों की जिम्मेदारी भी ले लें तो देश के ज्यादातर गरीबों और वंचितों को महामारी की मार से बचाया जा सकता है। समझ में नहीं आता कि हमारा खबरतंत्र, खास तौर से हमारे टीवी चैनल महामारी से लड़ने की बजाय अपनी सारी शक्ति किसी एक व्यक्ति की हत्या या आत्महत्या की पहली को सुलझाने या उलझाने में क्यों लगे हुए हैं। दुनिया के कई अन्य मालदार देशों में, जहां यह महामारी भारत से अधिक जानलेवा रही है, वहां भी उनकी अर्थव्यवस्थाओं में 10-15 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट नहीं आई है। भारत सरकार ने भी अपने वंचित वर्गों के लिए 'बड़ी-बड़ी राहतों' की घोषणाएं की हैं लेकिन वे ऊंट के मुंह में जीरा के समान ही हैं।

यदि महामारी की रफ्तार भारत में इतनी ही तेज रही तो अमेरिका को पीछे छोड़ने में भी उसे ज्यादा देर नहीं लगेगी। इस समय भारत में प्रतिदिन संक्रमित होने वालों की संख्या एक लाख को छूने वाली है।

जांच की धीमी रफ्तार

वेदप्रताप वैदिक।

भारत की दुविधा भी गजब की है। एक तरफ रेलें, मेट्रो, हवाई जहाज, दफ्तर, बाजार और कल-कारखाने खुल रहे हैं, दूसरी तरफ कोरोना की महामारी बढ़ती चली जा रही है। खुद भारत महामारी से महत्तम मारी की तरफ दौड़ लगा रहा है। इस दौड़ में उसने दुनिया के ज्यादातर देशों को मात कर दिया है। बस अमेरिका उसके आगे है। ब्राजील और भारत में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 41 लाख के आस-पास जाकर बराबरी पर पहुंचा, लेकिन फिर भारत अपनी तेजी से ब्राजील को पीछे छोड़ता गया। यदि महामारी की रफ्तार भारत में इतनी ही तेज रही तो अमेरिका को पीछे छोड़ने में भी उसे ज्यादा देर नहीं लगेगी। इस समय भारत में प्रतिदिन संक्रमित होने वालों की संख्या एक लाख को छूने वाली है।

इसमें शक नहीं कि इस महामारी का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार और सभी प्रांतों की सरकारें जी-जान से जुटी हुई हैं। कोरोना की जांच का आंकड़ा 10 लाख रोजाना तक पहुंच गया है। अब तक 5 करोड़ के आसपास लोगों की जांच हो चुकी है लेकिन 138 करोड़ की आबादी वाले देश में जांच की यह रफ्तार चलती रहे तो भी सबकी जांच करने में बरसों खप



जाएंगे। उसके काफी पहले ही रोग-निवारक टीका आने की संभावना है। संतोष की बात यह है कि हमारे देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या प्रतिशत के हिसाब से बहुत कम है। यहां कोरोना से मरने वालों का प्रतिशत सिर्फ 1.7 है जबकि सारी दुनिया में 3.2 प्रतिशत है।

जनसंख्या के हिसाब से अमेरिका में ज्यादा लोग मर रहे हैं। अमेरिका की जनसंख्या भारत की एक चौथाई है और वहां की स्वास्थ्य-सेवाएं भारत से कई गुना बेहतर हैं। फिर भी वहां ज्यादा अनुपात में लोग इसीलिए मर रहे हैं कि एक तो राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का रवैया काफी गैर-जिम्मेदाराना रहा है, दूसरे अमेरिकी जनता में आत्मविश्वास की अति भी इस रोग के फैलने का मुख्य कारण है।

जैसे ट्रंप मुखपट्टी नहीं लगाते हैं, वैसे ही हजारों अमेरिकी नर-नारी समुद्र-तटों पर घूमते हुए नजर आते हैं। आत्मविश्वास की अति और लापरवाही हमारे यहां भी कम नहीं है। इसीलिए भारत में भी कई बड़े-बड़े नेता, फिल्मी सितारे, डॉक्टर और नर्स भी कोरोना के जाल में फंस गए हैं।

फरवरी-मार्च में तो यह महामारी सिर्फ दिल्ली और मुंबई जैसे कुछ बड़े शहरों में दिखाई पड़ रही थी लेकिन अब वह कस्बों और गांवों तक फैल गई है। अचानक तालाबंदी की घोषणा के कारण शहर छोड़ कर अपने गांवों की तरफ भागते हुए मजदूर इसे अपने साथ लेते गए। अब ज्यों-ज्यों जांच उन तक पहुंच रही है, मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। लेकिन संतोष का विषय है कि इलाज से ठीक होने वालों की संख्या भी काफी अच्छी है। यदि भारत में 100 लोगों को कोरोना होता है तो उनमें से 76-77 लोग ठीक हो जाते हैं।

कोरोना के इलाज के लिए भारत में क्या-क्या नहीं हो रहा है। असरदार टीके (वैक्सीन) की खोज तो जोरों से चल ही रही है, आयुष मंत्रालय और अन्य कई आयुर्वेदिक संस्थानों ने तरह-तरह के सस्ते और सुलभ क्वाथ (काढ़े) जारी किए हैं। होम्योपैथी के डॉक्टर भी चुप नहीं बैठे हैं। लाखों-करोड़ों लोग आसन, प्राणायाम और व्यायाम के जरिए भी कोरोना का प्रतिरोध कर रहे हैं।

सूडोकू बववाल-5471									
6	3	7		1	5	4	8	9	
	8							2	
		1		4	8				6
	6			9	7	1			
7	2							5	3
		5	6	3					9
5			8	2		3			
	4							7	
1		3	7	5		2	6	8	

अपना ब्लॉग

कोरोना बढ़ रहा है लेकिन डर घट रहा

मोहन। क्या यह कम संतोष का विषय है कि टीके के बिना ही हमारे डॉक्टरों ने कोरोना की तात्कालिक काट कुछ हद तक निकाल रखी है। यह तो स्पष्ट है कि देश में कोरोना बढ़ रहा है लेकिन उसका डर घट रहा है। यदि ऐसा नहीं होता तो क्या लोग सड़कों, बाजारों, दफ्तरों, कारखानों, रेलों और बसों में दिखाई पड़ते? सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 24 प्रतिशत की गिरावट हो गई है। कुछ आंकड़ों के अनुसार दो करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई हैं और लगभग दस करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। हमने ब्रिटेन को भी मात कर दिया है, जहां की जीडीपी की गिरावट 20 प्रतिशत है। लेकिन समृद्ध देशों की सरकारें गैर-सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों की 80 प्रतिशत तनखाहें खुद दे रही हैं।

